संख्या- 165/78-1-07/14 आई.टी.-1/2004 (टीसी)

प्रेषक

शंभु नाथ
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2007

विषय : विभिन्न विभागों के लिए वेबसाइट के लिए विकास एवं कॉण्टैण्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 430/78–आई.टी.–2001 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें सभी विभागों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी–अपनी वेबसाइट तैयार कराते हुए विभागीय वेबमास्टर नियुक्त करें जो इन वेबसाइट को अध्यावधिक कर सकें। इस शासनादेश के फलस्वरूप कई विभागों ने एन.आई.सी. के माध्यम से अपनी वेबसाइट बनायी हैं जो कि एन.आई.सी. के सर्वर पर होस्ट की गयी है। इस प्रकार एन.आई.सी. द्वारा लगभग 55 वेबसाइट का विकास समय–समय पर किया जा चुका है। समस्त वेबसाइट के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि कुछ विभाग जैसे नियुक्ति विभाग ने अपनी वेबसाइट एन.आई.सी. के माध्यम से अध्यावधिक और विकसित कराके http://niyuktionline.nic.in नामक अति उपयोगी एवं आकर्षक वेबसाइट तैयार करा ली गयी है परन्तु अधिकांश वेबसाइट अध्यावधिक नहीं हैं और अलग–अलग फॉण्ट्स के प्रयोग के कारण इनका सुविधापूर्वक प्रयोग भी नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ वेबसाइट हिन्दी व कुछ अंग्रेजी भाषा में है।

वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि सभी विभाग अपनी अधिक से अधिक अध्यावधिक सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। इस वृहद कार्य को समयवद्ध रूप से सुनिश्चित कराने के लिए इसे यूपीडेस्को के माध्यम से आऊटसोर्स करने की आवश्यकता महसूस की गयी। तद्नुसार विभिन्न विभागों एवं जिलों की वेबसाइट के उन्नयन एवं उन्हें द्विभाषीय बनाने की योजना के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा मेसर्स सी. एम.सी. लिमिटेड को विभिन्न विभागों की वेबसाइट के उन्नयन एवं उन्हें द्विभाषी व समान "लुक एण्ड फील" का करने के लिए कार्यादेश दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या 707/78–1–2005–14 आई.टी./2004 (टीसी) दिनांक 14 जुलाई, 2006 द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं।

खेद का विषय है कि योजना के अन्तर्गत अपनी वेबसाइट उच्चीकृत कराने एवं इसे द्विभाषी बनाने की दिशा में अधिकांश विभागों ने पर्याप्त रूचि नहीं दिखायी है। अभी भी कई विभागों की वेबसाइट या तो बनी ही नहीं है अथवा उनका उन्नयन नहीं हुआ है। प्रश्नगत योजना की प्रगति निम्नवत् पायी गयी है:–

(1) अभी तक कुल 29 विभागों द्वारा वेबसाइट उन्नयन/विकास हेतु अनुरोध किया गया है तथा मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड के माध्यम से इनमें से अधिकांश विभागों में कार्य आरम्भ हो गया है, परन्तु मात्र 04 विभाग/जिले यथा सूचना प्रौद्यागिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, महिला कल्याण विभाग, जनपद इलाहाबाद (अर्द्ध कुम्भ) तथा स्थानीय निकाय विभाग की ही वेबसाइट विभाग की आवश्यकता के अनुसार तैयार कर एन.आई.सी. के सर्वर पर लोड की गयी है।

कमशः..2...

(2) 06 अन्य विभाग यथा लघु सिंचाई, औद्योगिक विकास, विकलांग कल्याण, जे.टी.आर.आई, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा नागरिक सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा तैयार कर ली गयी है। इसे लोड करने के लिए वांछित अनुमोदन विभाग स्तर पर लम्बित होने के कारण इन वेबसाइट्स को एन.आई.सी. सर्वर पर लोड नहीं किया जा सका है।

(3) उपरोक्त 29 में से 07 अन्य विभाग जिनमें अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, दुग्ध विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, भूगर्भ जल विभाग तथा लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग सम्मिलित हैं, में सूचनाएं आदि एकत्र कर वेबसाइट विकास एवं रिफर्बिश्मैण्ट का कार्य किया जा रहा है।

(4) 06 अन्य विभाग यथा गृह, प्रशासनिक सुधार, डी.जी.पी. मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजक, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के सम्बन्ध में एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया है कि वेबसाइट का कार्य वे एन.आई.सी. से कराना चाहते हैं परन्तु इन विभागों की वेबसाइट का न तो उन्नयन हुआ है और न ही इन विभागों ने शासनादेश दिनांक 14.07.2006 के अनुसार विभागीय मांग लिखित रूप से यूपीडेस्को को भेजी है।

(5) 06 अन्य विभाग यथा आई.सी.डी.एस., खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा परिवहन ऐसे विभाग हैं जिनकी मांग के अनुसार यूपीडेस्को द्वारा मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड को कार्यादेश तो निर्गत किये जा चुके हैं, परन्तु विभागों द्वारा अभी सूचनाएं उपलब्ध न करा पाने के कारण कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है।

योजना की समीक्षा एवं अब तक की गयी प्रगति के आधार पर सभी विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि योजना के अन्तर्गत समस्त शासकीय वेबसाइट को अध्यावधिक व द्विभाषी करने की आवश्यकता को समझते हुए निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही उच्च प्राथमिकता पर करें जिससे कि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके:–

1. जिन विभागों की वेबसाइट अभी तक नहीं बनी है वे शासनादेश दिनांक 14.07.2006 की प्रक्रिया के अनुसार मांग–पत्र यूपीडेस्को को भेज दें तथा सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.05.2007 तक उनकी वेबसाइट तैयार करा ली जाय।

2. जिन विभागों की वेबसाइट एन.आई.सी. द्वारा तैयार की जा चुकी है वे या तो एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा शासनादेश दिनांक 14.07.2006 की प्रक्रियानुसार मांग–पत्र यूपीडेस्को को भेज कर दिनांक 15.05.2007 तक अपनी वेबसाइट को द्विभाषी एवं अध्यावधिक बनवाना सुनिश्चित करा लें। सम्बन्धित विभाग का यह दायित्व होगा कि वे चयनित संस्था से सक्रिय सम्पर्क रखते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करायें और यदि कोई कठिनाई हो तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसका समाधान करायें।

3. राज्य में ई–गवर्नेन्स की तैयारी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 964/78–2––2005–5 आई.टी./2005 टीसी दिनांक 18.07.2005 द्वारा समस्त विभागों को निर्देश भेजे गये हैं कि वे ई–गवर्नेन्स योजनाओं एवं विभागीय वेबसाइट के कार्य के लिए अपने–अपने विभाग में नोडल अधिकारी एवं वैबमास्टर नियुक्त कर लें। यद्यपि अधिकांश विभागों द्वारा यह नामंकन कर दिया गया है परन्तु कुछ विभागों द्वारा अभी तक अपने विभाग के नोडल अधिकारी/वेबमास्टर की नियुक्ति नहीं की गयी है। अतः ऐसे सभी विभाग, जिनके द्वारा अभी तक अधिकारियों का नामंकन नहीं किया गया है, से अपेक्षा की जाती है कि वे एक सप्ताह के अन्दर नामंकन कर दें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देशित कर दें कि वे विभागीय वेबसाइट का कार्य अपनी देख–रेख में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पन्न करायें। समस्त विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया विभागीय नोडल अधिकारी एवं वेबमास्टर की सूचना संलग्न प्रारूप पर भी यूपीडेस्को एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध करा दें।

क्रमशः...3....

4. कतिपय विभागों द्वारा केवल एक ही भाषा में अपनी विभागीय वेबसाइट को विकसित किये जाने पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य अपने बारे में विश्व के समस्त जनमानस के लिए सूचनाएं उपलब्ध करायें जिसके लिए वेबसाइट एवं इण्टरनेट एक सशक्त माध्यम हो गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि शासन की विभिन्न वेबसाइट्स का मानकीकरण हो तथा उन्हें द्विभाषी बनाया जाए क्योंकि यह वेबसाइट न केवल प्रदेश के जनमानस द्वारा देखी जाएंगी वरन् राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभागीय जानकारी हेतु एवं प्रदेश में पूँजीनिवेश आकर्षित करने की दृष्टि से भी देखी जा सके। अतः सभी विभागीय वेबसाइट द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी में) अनिवार्य रूप से विकसित करायी जाय।

5. जिन विभागों द्वारा वेबसाइट का कार्य मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है उनको यह सुनिश्चित एवं प्रमाणित करना होगा कि वेबसाइट के जो–जो पृष्ठ/कॉण्टैण्ट मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से शुद्ध हैं ताकि उन्हें एन.आई.सी. के सर्वर पर लोड किया जा सके। इस प्रमाणीकरण में एक सप्ताह से अधिक का समय किसी भी परिस्थिति में नहीं लगना चाहिए।

6. इस योजना के अन्तर्गत सभी विभागों की वेबसाइट को समान "लुक एण्ड फील" देते हुए एवं द्विभाषी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट, जिनके URL क्रमशः **http://infotech.up.nic.in** एवं **http://mahilakalyan.up.nic.in** हैं, देखी जा सकती हैं।

सभी विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव से अपेक्षा है कि वे वेबसाइट उन्नयन के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए हर परिस्थिति में 15.05.2007 तक अपने मार्गदर्शन में इसे पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(शंभु नाथ)
मुख्य सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संख्या : 165(1)/78-1-07/14 आई.टी.-1/2004 (टीसी)तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
2. श्री एस.बी. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. योजना भवन लखनऊ।

आज्ञा से,

(ज़ोहरा चटर्जी)
प्रमुख सचिव

संलग्नक

विभिन्न विभागों में ई–गवर्नेन्स योजनाओं के लिए नामित नोडल अधिकारी एवं वेबसाइट के लिए विभागीय वेबमास्टर के नामांकन का विवरण

1	विभाग का नाम	
2	विभाग का पता	
3	विभागीय वेबसाइट का यू.आर.एल.	
4	विभागाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम	
		ई–मेल :– दूरभाष नं. :–
5	ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 964/78–2––2005–5 आई.टी./2005 टीसी दिनांक 18.07.2005 के अन्तर्गत नामित विभागीय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	
		ई–मेल :– दूरभाष नं. :–
6	वेबसाइट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 430/78–आई.टी.–2001 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के अन्तर्गत नामित विभागीय वेबमास्टर का नाम, पदनाम एवं पता	
		ई–मेल :– दूरभाष नं. :–

सूचना निम्नलिखित को प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. संयुक्त सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, चतुर्थ तल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
2. श्री रवीन्द्र सिंह, प्रभारी, ई–गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, 9 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।